राज्य के सन्दर्भ में अविद्युतीकृत गांवों की संख्या (71352–63433–7919) के बीच अन्तर) (112) इस तथ्य के कारण है कि 1971 की जनगणना के अनुसार कुछ गांवों जिन्हें पहले विद्युतीकृत किया जा चुका था, को अतिरिक्त (विद्युतीकृत) गांवों में शामिल कर लिया गया था और कुछ गांव, 1981 की जनगणना के अनुसार गैर-आबाद गांव थे।

विवरण II

मध्य प्रदेश में कुटीर ज्योति कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्धियों का जिलेवार ब्यौरा

क्र०सं०	जिला	कुल
1	2	3
1.	भोपाल	642
2.	रायसेन	2227
3.	विदिशा	1726
4.	सीहोर	1476
5.	राजगढ़	1548
6.	होशंगाबाद	2005
7.	बैतूल	3320
8.	ग्वालियर	1176
9.	दतिया	1594
10.	मुरैना	1600
11.	भिण्ड	1350
12.	गुना	1872
13.	शिवपुरी	1754
14.	इन्दौर	1004
15.	खण्डवा	2473
16.	खारगोन	6003
17.	धार	4422
18.	झाबुआ	5588
19.	उज्जैन	1561
20.	मन्दसौर	1243
21.	रतलाम	2202
22.	शाजापुर	1604
23.	देवास	1665
24.	जबलपुर	3232
25.	मण्डला	3830
26.	छिन्दवाड़ा	3034
27.	सिवनी	3387
28.	बालाघाट	2718
29.	नरसिंहपुर	1670
30.	सागर	2770
31.	दमोह	5197
32.	रीवा	2200
33	सतना	4243
34.	छतरपुर	1411
35.	टीकमगढ़	1538
36.	पन्ना	2700
37.	सीधी	3072
38.	शहडोल	7343
39.	रायपुर	7134
40.	दुर्ग	2721
41.	राजनन्दगांव	2301
42.	बस्तर	7874
43.	बिलासपुर	4809
44.	सरगुजा	4814
45.	रायगढ़	4190
	जोड़ :	132243

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राशि का आबंटन

*270. **श्री रामदास अग्रवाल :**
श्री ईश दत्त यादव

क्या वित्त मंत्री 26 नवम्बर 1991 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न सं० 62 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि

के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए, अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) उपर्युक्त आबंटित राशि में से कितनी धनराशि पहले ही खर्च की जा चुकी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : (क) और (ख) विशेष कृषि परियोजना (एस०पी०ए०) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का एक कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्डों के ग्रामीण क्षेत्रों में पम्पसैटों को बिजली प्रदान करने के लिए परेषण लाइनें खींचने और अन्य आधारभूत ढांचे संबंधी समर्थन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम वाणिज्यिक बैंकों और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा राज्यों में बिजली बोर्डों को वित्तीय सहायता प्रदान कर इस कार्यक्रम का वित्तपोषण किया जाता है। सातवीं योजना में 1986-87 से 1989-90 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत नाबार्ड द्वारा उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को आबंटित रकम और उसके अन्तर्गत प्राप्त उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	उत्तर प्रदेश		राजस्थान	
	आबंटन	उपलब्धि	आबंटन	उपलब्धि
1985-86 . . .	*	376	*	387
1986-87 . . .	500	260	400	185
1987-88 . . .	600	227	200	94
1988-89 . . .	610	550	145	95
1989-90 . . .	405	367	328	325

*ग्रामीण विद्युतीकरण निगम/विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रमों के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया था, क्योंकि उसे छोटी सिंचाई के आबंटन के साथ ही जोड़ दिया गया था।

Closure of sick public sector Enterprises

*279. DR. RATNAKAR PANDEY:
SHRI SUKOMAL SEN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to refer to the answer to *Starred Question* 61 given in the Rajya Sabha on 26th November, 1991 and state:

(a) whether he announced at Bangkok that the sick public sector enterprises would be closed down;

(b) if so, whether the Union Cabinet has since approved the proposal and